

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.- 7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित
सुरत-गुजरात, संस्करण सोमवार 25 नवंबर 2024 वर्ष-7, अंक-299 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रुपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com [f](http://www.facebook.com/krantisamay1) [t](http://www.twitter.com/krantisamay1)

पहला कॉलम



दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर गंभीर, नोएडा के स्कूल में 27 तक औंगलाइन

- हवा में प्रदूषण के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में सांस लेने में मुश्किलें बढ़ीं

नई दिल्ली ! एक दिल्ली एक दिल्ली इंडेक्स (एक्यूआई) अपी भी गंभीर बनी हुई है। शनिवार को शहर में एक्यूआई 500 के स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही गुरुग्राम में भी 491 का एक्यूआई दर्ज किया गया। हवा में प्रदूषण के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में सांस लेने में मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक्यूआई को 0-50 के बीच अच्छा, 51-100 के बीच संतोषजनक, 101-200 के बीच बेद्द खराब और 201-300 के बीच खराब, 301-400 के बीच बेद्द खराब और 401-500 के बीच गंभीर शामिल करता है। गुरुग्राम को हवा की गति में बढ़िद्ध के कारण राजधानी में गंभीर श्रेणी की 5 दिनों की चेत दृष्टि थी। हालांकि, शनिवार को फिर से यह 412 पर पहुंच गया, जो कि गंभीर कैटेगरी में आता है। यह आंकड़ा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीओसीबी) के 24 घंटे के औसत डेटा पर आधारित है।

जर्मू कृष्णी में आतंकियों के ठिकाने से गोला बारूद व हथियार बरामद

- गोला गांव से सटे जंगलों में चलाया गया संयुक्त अग्नियान

श्रीनगर। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर बारामुख्या जिले के कुंच इलाके में एक आतंकवादी ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किया है। एक बढ़िद्ध पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपेक्षाने में असेना, पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। अपेक्षाने के ठिकाने का खुलासा हुआ। जानकारी अनुसार बारामुख्या पुलिस, बड़ागाम पुलिस और 62 आरआर द्वारा पुलिस स्टेशन कुंच के अधिकार क्षेत्र के मालवा गांव से सटे जंगलों में एक संयुक्त अभियान चलाया गया। बन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान, एक आतंकवादी ठिकाने का भड़ाफोड़ किया गया और घटनास्थल से हारियार और गोला-बारूद सहित आपसिंजनका समाप्ती बरामद की गई। कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत समाप्ती बरामद करने के बाद, ठिकाने को मौके पर ही नह कर दिया गया है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 8 लोग गंभीर घायल

- एक कैंटर ने इनोवा और टोयोटा कारों को टक्कर नार दी

आगरा। आगरा से नोएडा की दिशा में जा रहे कैंटर ने यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कैंटर ने इनोवा और टोयोटा कारों को टक्कर नार दी, जिससे कारों में स्कॉर 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल यात्रियों को तलाकाल एंबुलेंस से नर्जीदारी के बाद राजाज चल रही है। इन यात्रियों की हालत स्थिर बताया जा रही है और मोके पर पुलिस ने दुरुटनों के कारणों की जाच शुरू की है। यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रावात में कठन समय के लिए रुकवाट अर्थात् थी, जिसे एक सामान्य रुकवाट की गया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे की बजह अपी भी स्टूप नहीं है, लेकिन वे सभी पहलुओं पर गैर कर रहे हैं और सही कारणों का पता लगाने के लिए जाच कर रहे हैं। इस हादसे से यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा की चिंता बढ़ दी है, और लोगों को बाहन चलाने समय सावधान रखने की सलाह दी जा रही है। पुलिस जल्द ही इस हादसे की पूरी जानकारी सार्वजनिक करेगी।

भारतीय के लिए यूरोपीय वीजा में बढ़ती चुनौती और भारी भेदभान शुल्क

नई दिल्ली ! भारतीय यात्रियों के लिए यूरोपीय वीजा प्रक्रिया अब पहले से अधिक महानी और जटिल हो गई है। व्हाल ही में यूरोपीय संघ में वीजा शुल्क में बढ़िद्ध बढ़ गया है। गरीब और विकासशील देशों के यात्रियों के लिए यह स्थिति और भी कठिन साबित हो रही है। फीस और आवायकताओं में बढ़ावारी के बाद यूरोप के देशों की यात्रा असंभव हो रही है। नई व्यवस्था में आवेदन शुल्क के साथ अतिरिक्त शुल्क भी जोड़ गए हैं। भारतीय यात्रियों को अब वीजा प्रेसेसिंग के लिए लगभग 1900 रुपये और अच्युत शुल्क मिलाकर 7600 रुपये तक बढ़ाने पड़ रहे हैं। इसमें सेवाओं की लागत, आवेदन जमा करने की प्रक्रिया और यात्रा बीमा जीसी शामिल है। यह बढ़िद्ध उत्तरांचल के लिए यह स्थिति और भी कठिन साबित हो रही है। यह बढ़िद्ध उत्तरांचल के लिए बड़ी बाधा है, जो यूरोप में पेट्रोन, शिक्षा या व्यापार के लिए जाना चाहत है। यूरोपीय वीजा प्रणाली की नई नीति गरीब और अमीर देशों के बीच की अधिक असमानता को उत्तरांचल करने वाली है। गरीब देशों के नारायणों से अधिक शुल्क लिया जा रहा है। जबकि सुविधा-सम्पर्क देशों के लिए वीजा की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो रही है। यह भेदभानपूर्ण है। विकासशील देशों के लिए असमानता को बढ़ावा सकता है। वीजा की इस नीति से पर्यावरण और व्यापक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यूरोपीय देशों को अपनी अतिरिक्तव्यस्था को स्थिर रखने के लिए बाहरी यात्रियों और निवेशकों की आवश्यकता है। बढ़ती फीस और जटिल प्रक्रिया यूरोपीय देशों के हितों के प्रभाव प्रतीत है।

सरकार ने कहा- किसी भी विषय पर चर्चा को तैयार करने की अपील की।

नई दिल्ली ।

संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विषय के कई मुद्दों को उठाने की तैयारी दिखाई दी है। कांग्रेस ने अडानी मामले पर संसद में चर्चा की मांग रखी है। बैठक उत्तरांचल के बीच संसदीय सत्र के लिए चर्चा की मांग रखी है। इसके साथ ही विषय के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार संसद में किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। इसी के साथ उड़न्होंने संसद के साथ उड़न्होंने अडानी मामले पर चर्चा की मांग रखी है।

सार्विक पूर्ण तरीके से चलाने की अपील की।

सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने अडानी समूह पर लगे आरोपों और मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अडानी समूह के बिलापा अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों का विषय के लिए चर्चा देते हुए इस पर भी उत्तरांचल के आरोपों का विषय किया है। साथ ही मणिपुर में जातीय दिंसा और मुख्यमंत्री बोरेन सिंह की भूमिका पर भी सवाल उत्तरांचल के बीच चर्चा की मांग रख दी है। इसके साथ ही विषय के बारे में बढ़ते हुए इस पर भी उत्तरांचल के आरोपों का विषय किया है। साथ ही मणिपुर में जातीय दिंसा और मुख्यमंत्री बोरेन के लिए चर्चा की मांग रखी है। कांग्रेस ने अडानी मामले पर चर्चा की मांग रखी है।

हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। उड़न्होंने कहा, कि हमारा उद्देश्य सत्र शांति और उत्तरांचल के साथ पूरा हो सकता है। सदन में सार्वजनिक चर्चा हो और सभी सदस्य अपनी भागीदारी निभाएं। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से भाजपा आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन विषय के आक्रमक रूप के देखते हुए कहा जा रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र हांगमेदर रखने वाला है।

सर्विधान दिवस पर होगा विशेष आयोजन

26 नवंबर को संविधान दिवस के उत्तरांचल में संसद का काई सत्र नहीं होगा। इस दिन संविधान भवन में विशेष समारोह

का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रक्रियाओं और ऐतिहासिक तथ्यों को गृहीत की जाएगी। इस दिन संविधान भवन में विशेष समारोह

मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा- डिजिटल अरेस्ट का सरकार में कोई प्रावधान नहीं

विकसित भारत में युवाओं की भूमिका अहम



नई दिल्ली ।

मोदी ने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखते हुए युवाओं पर फोकस किया। उड़न्होंने कहा कि विकसित भारत में युवाओं की भूमिका अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 24 नवंबर को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 116वें एपिसोड में स्वामी विवेकानंद को 162वीं जयंती, एनसीसी दिवस, गयान, यात्रा, लाइब्रेरी आदि विषयों पर अपनी बात को बार-बार यह समझाना की जाती है। यह एक गुणात्मक विषय है। एनसीसी को बार-बार यह समझाना होता है कि सरकार में अरेस्ट करने के लिए एडवोकेट अरेस्ट के बीच रेडियो की डेटर रहती है। यह एक खुला झूल और लोगों को अपने जाल में फँसाने की बात साजिश है। यह गौरतलब है कि

इससे पहले मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट जैसे फॉड ऐप से बचने के लिए तीन स्टेप रूपों में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना विकसित करती है। इसके साथ ही पीएम मोदी न

नौसेना के बेड़े में शामिल हुईं छठी मिसाइल - गोला बारूद नौका

नई दिल्ली। मुंबई डॉकर्याड में आयोजित एक समारोह में छठी मिसाइल और गोला बारूद नौका (एलएसएम-12, यार्ड 80) नौसेना को सौंपी गई। इस बाबत आयोजित किए गए समारोह की अध्यक्षता नौसेना की पश्चिमी कमांड के मुख्यालय के मुख्य मरम्मत अधिकारी कमोडोर अभिरुप मजुमदार ने की। नौसेना ने बताया कि ऐसी कूल आठ नौकाओं के निर्माण के लिए विशाखापट्टनम की मैसैनरी सेकॉन्ड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया एक समझौता इस साल 19 फरवरी 2024 को पूरा हो गया था। यह एक एमएसएमई शिपयार्ड है। इन नौकाओं के नौसेना के जंगी बैडे में शमिल होने से उसकी परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। क्योंकि इनकी मदद से बंदरगाह के किनारे और बाहरी बंदरगाहों पर भारतीय नौसेना के प्लेटफार्मों तक वस्तुओं, गोला बारूद के परिवहन, चढ़ने और उतरने में सुविधा होगी। नौसेना ने कहा कि नौकाओं का स्वदेशी रूप से डिजाइन करने के लिए एक भारतीय जहाज डिजाइनिंग फर्म से सहयोग लिया गया था। इसके अलावा बल की विज्ञान-तकनीकी प्रयोगशाला (विशाखापट्टनम) में इनका सफलतापूर्वक मॉडल तैयार किया गया। जिससे इनकी समुद्री योग्यता सुनिश्चित की जा सके। इस निर्माण कार्य को भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) के तय नियमों और विनियमों के तहत किया गया है। सातों नौकाएं केंद्र सरकार की मेंक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल की गौरवशाली धजवाहक हैं।

**मंत्रियों और विधायकों के घरों
को लूटने और आगजनी करने
वाले 7 और गिरपतार**

इंफाल। मणिपुर की इंफाल घाटी में विधायकों के आवासों पर हुई तोड़फोड़ 35 और आगजनी की घटना में शामिल होने के आरोप में सात और लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आधिकारिक बयान में विवरात को यह जानकारी दी गई। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कार्रवाई जिले से शुरूवात को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बयान में कहा गया है कि इस मामले में सात और लोगों की गिरफ्तारी के साथ अब तक कुल 41 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मणिपुर सौएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि 16 नवंबर को प्रदर्शन के दौरान मत्रियों और विधायिकों की संपत्ति लूटने में शामिल सदिग्दारों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सौएम ने कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलन के नाम पर कुछ गिरोहों ने मत्रियों और विधायिकों के घरों में लूटपाट और आगजनी की। सौरीष्टीवी फूटैज के जरिए सदिग्दारों की पहचान कर ली गई है और उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए शर्म आती है कि मणिपुर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

**जम्मू कश्मीर में आतंकियों के
ठिकाने से गोला बारूद व
हथियार बरामद**

- मालवा गांव से सटे जंगलों में चलाया
गया संयुक्त अभियान

झांसी अग्निकांड में हुई दो और बच्चों की मौत, संख्या बढ़कर हुई 17, घर वालों का रो रोकर बरा हाल

आदोलन के कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनके आदोलन का कोई

असर नहीं हान का चचा का राववार का खारज कर दिया। महाराष्ट्र में 288-सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में महायुति गठबंधन ने 230 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी। चुनाव परिणाम शनिवार को घोषित किए गए। महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उपमुख्यमंत्री अंजित पवार की गष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) भी शामिल हैं। प्रदर्शनित ने समाजवादी थेट्र की 16 में से 10 सीट

जहानुपरी न नराजन्मा दार परा ५० मि स ५० स० लात
जीतीं, में जालना की सभी पांच सीट शामिल हैं।
जालना, नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय
के लिए आरक्षणीय की मांग को लेकर जरागे के
आंदोलन का केंद्र रहा है। इस वर्ष हुए लोकसभा
चुनावों में सत्तारुद्ध गठबंधन के खराब प्रदर्शन का
श्रय काफी हद तक जरागे के आंदोलन को दिया गया
था। जरागे ने विशेष रूप से उपमुख्यमंत्री और
भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फड़वींस के खिलाफ
तीखी टिप्पणी की थी।

गया, जबकि मैंने न तो चुनाव लड़ा और न ही किसी
का समर्थन किया? मैंने मराठा समुदाय को इन
राजनीतिक दलों के चंगुल से मुक्त कराया। मराठा
समुदाय को अपनी पसंद के अनुसार बोट देने की
आजादी मिली। मेरा ध्यान मराठाओं को सशक्त
बनाने पर है।' उन्होंने चुनाव परिणामों पर संतोष
व्यक्त करते हुए कहा कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र
विधानसभा के लिए 204 मराठा उम्मीदवार
निर्वाचित हुए हैं।

या समुदाय की आरक्षणीय मांग का विरोध करने वाल
को हारने की बात करते रहे थे। विपक्षी महा विकास
आघाडी (एमवीए) सिर्फ 46 सीट ही जीत सक
एमवीए में कांग्रेस, राकांपा (शरदचंद्र पवार) और
शिवसेना (उत्तार) शामिल हैं। भाजपा को 13
सीट मिलीं, शिवसेना को 57, जबकि राकांपा व
41 सीट मिलीं। एमवीए में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस
पर्टी (शरदचंद्र पवार) के उम्मीदवारों ने 10 और
कांग्रेस ने 16 सीट जीतीं, जबकि शिवसेना

जराग न कहा, 'काइ यह कस कह सकता है कि विधानसभा चुनाव में जराग फैक्टर विफल हो जराग 20 नवंबर का हान बाल विधानसभा (उआ) न 20 साठ पर जात दज का। चुनावों से पहले नियमित रूप से उम्मीदवार उतारने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रकोप से बचाने के नई दिक्षी (एजेंसी)। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खारे के मध्य भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) की सह-अध्यक्षता में 10वाँ ऊर्जा पैनल की बैठक बुमेल्स में संपन्न हुई। इसमें विदेश मंत्रालय की ओर से सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल और यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्रियों के महानिदेशक डिएटे जूल जोर्जेनसेन शामिल हुए। दोनों पक्षों ने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु भागीदारी 2025-28 तक एक कार्य योजना को स्वीकार किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक का उद्देश्य ऊर्जा पैनल के विषय पर दोनों पक्षों की ऊर्जा परिवर्तन प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा 2021-24 तक भारत-ईयू स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु भागीदारी के त्रूपरे चरण की उपलब्धियों की समीक्षा करना था। इसमें भारत के केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली मंत्रालय के प्रतिभागियों के अलावा ईयू से ऊर्जा और कलाइमेट एकशन के निदेशालय प्रमुख शामिल हुए। दोनों पक्ष एक दीर्घावधि सोध साझेदारी प्रतिबद्धताओं से भी जुड़े हुए हैं। जिसमें स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में शाध के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना पिछले साल 2023 में स्थापित किए गए स्वच्छ और हरित तकनीक के लिए गठित किए गए भारत-ईयू व्यापार और तकनीकी परिषद कार्य समूह का हिस्सा है। चार वर्षीय भागीदारी में भारत और ईयू

কলকাতা (এজেন্সী)। পশ্চিম
বঙ্গাল কে রাজ্যপাল সীবী আনন্দ বোস নে
— হে — হে — হে — হে —



राजभवन में खुद का प्रतिमा लगवाइ आर खुद ही उसका अनावरण किया। अपने कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने अपनी प्रतिमा का शनिवार को अनावरण किया है। इस मौके पर पौधारोपण और पैटेंग प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा चिकित्सी की स्पष्टी करवाई गई थी जिसमें स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया था।

अपनी ही प्रतिमा का अनावरण करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आलोचकों का कहना है कि पढ़ पर रहते हुए अपनी ही प्रतिमा लगवाना गलत है। अनावरण के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसपर लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई लोगों का कहना है कि राज्यपाल अपने ही महिमांडण में लगे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्थ साहा नाम के एक कलाकार ने यह मूर्ति राज्यपाल को भेट की थी। पार्थ साहा कोलकाता के

ईंडियन म्यूजियम से संबंधित हैं। राज्यपाल की तस्वीर के आधार पर उन्होंने फाइबर की यह प्रतिमा बनाई है। वह कभी आपने सामने राज्यपाल से नहीं मिले थे। राज्यपाल कार्यालय ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने खुद अपनी प्रतिमा नहीं बनवाई है बल्कि एक कलाकार ने भेट की है। वहीं टीएमसी ने इसपर आपत्ति जताते हुए कहा कि जीवित रहते हुए ही राज्यपाल अपने महिमांडण के लिए खुद की प्रतिमा लगवाए दे रहे हैं। टीएमसी ने कहा, हमने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। वह परिवर्तिस्थि के भूखे हैं। अब आगे क्या होगा। क्या वह अपनी प्रतिमा को हार पहनाएंगे। उन्हें अब हार भी पहना देना चाहिए। टीएमसी प्रवक्ता जयप्रकाश मजुमदार ने कहा कि राज्यपाल मणिलों की तरह काम कर रहे हैं। सीपीएम सेंट्रल कमेटी के दस्य सुजान चक्रवर्ती ने कहा, यह बहुत ही अपमानजक है। यह हमारे राज्य का दुर्भाग्य भी है। बंगाल की संस्कृति के साथ भी गंदा खेल खेला जारहा है। बता दें कि मूर्ति का अनावरण करते हुए सीबी आनंदबोस ने कहा था कि बंगाल की राजनीतिक दशा बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा, बंगाल की जनता लंबे समय तक यह सब बर्दिश्वर नहीं करेगी। उन्होंने दो साल के अन्ने खट्टे मीठे अनुभव बर्यां किए।

जलवाय परिवर्तन के बढ़ते प्रकोप से बचाने के लिए भारत-ईय के बीच हआ विचार मंथन

नई दिल्ली (एजेंसी)। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के मध्य भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) की सह-अध्यक्षता में 10वीं ऊर्जा पैनल की बैठक बुसेल्स में संपन्न हुई। इसमें विदेश मंत्रालय की ओर से सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल और यूरोपीय संघ के ऊर्जा मामलों के महानिदेशक डिट्रॉइट जूल जेरोनसे शामिल हुए। दोनों पक्षों ने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु भागीदारी 2025-28 तक एक कार्य योजना का स्वीकार किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक का उद्देश्य ऊर्जा पैनल के विषय पर दोनों पक्षों की ऊर्जा परिवर्तन प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा 2021-24 तक भारत-ईयू स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु भागीदारी के दूसरे चरण की उपलब्धियों की समीक्षा करना था। इसमें भारत के केंद्रीय नवीन ऊर्जा, बिजली मंत्रालय के प्रतिभागियों के अलावा ईयू से ऊर्जा और क्लाइमेट एकशन के निदेशालय प्रमुख शामिल हुए।

मंत्रालय ने बताया कि भारत और ईयू ने तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरी की गई 9 क्षेत्रों की 51 गतिविधियों का विस्तार से जायजा लिया। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग के लिए फेमर्क को भी स्वीकृति दी गई। फेमर्क में भारत और ईयू में ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग के लिए बनाए गए सिद्धांत मर्यादा रूप से शामिल हैं। यहां बता दें कि ईयू और संघ के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन में भाग लिया था। वहाँ, भारत मौजूदा वर्ष में यूरोपियन हाइड्रोजेन सासाह में विशेष भागीदार के रूप में शामिल हुआ। दोनों पक्ष एक दीर्घावधि शोध साझेदारी प्रतिबद्धताओं से भी जुड़े हुए हैं। जिसमें स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में स्थानीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना पिछले साल 2023 में स्थापित किए गए स्वच्छ और हरित तकनीक के लिए गठित किए गए भारत-ईयू व्यापार और तकनीकी परिषद कार्य समूह का हिस्सा है।

चार वर्षीय भागीदारी में भारत और ईयू मुख्यतः प्राथमिकता वाले 5 क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें ग्रीन हाइड्रोजेन, अपतटीय हवा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इंटीग्रेशन, स्पार्ट ग्रिड, एनर्जी और क्लाइमेट कूटनीति मुख्य हैं। दोनों ने हरित हाइड्रोजन सहयोग के लिए एक व्यापक एजेंडा तैयार किया है। जिसमें बुलिनियादी ढांचे का विकास, नियामक और तकनीकी सहयोग, सम्प्लाई चेन को मजबूती प्रदान की जाएगी। भारत और ईयू ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में अपने सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई और जी-20 के तंत्र के तहत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में गहनता से सहयोग को लेकर सहमति जताई।



पांडेसरा की जनसेवा अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने सील और संचालकों को नोटिस दिया और नोटिस के बाद झोलाछाप डॉक्टर लापता

सचिन इलाके में अब भी कई ऐसे फोटो क्लीनिक जैसे केंद्र सक्रिय

जनसेवा अस्पताल के तीन झोलाछाप डॉक्टरों - बबलू शुक्ला, गंगाप्रसाद मिश्रा और राजाराम दुबे - को 28 तारीख को अस्पताल के पंजीकरण और डॉक्टरों के प्रमाणपत्रों के साथ हाजिर होने का अल्टीमेटम

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत, पांडेसरा की जनसेवा मल्टीस्पेशलिस्ट अस्पताल को फायर विभाग द्वारा सील करने के बाद, पहली बार जिला स्वास्थ्य विभाग ने क्लीनिकल एस्ट्रेचिलिंगमेंट एकत्र के तहत कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील किया। साथ ही, तीन संचालकों को 28 नवंबर को सभी प्रमाणों के साथ हाजिर होने का अल्टीमेटम दिया गया है।

जनसेवा के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों पर कानून का शिकंजा कस



दिया गया है। फायर विभाग के समक्ष उपस्थित होने का द्वारा सीलिंग की कार्रवाई आदेश दिया गया है।

के बाद, जिला पंचायत के स्वास्थ्य विभाग ने मौके का संचालकों को अस्पताल का पंजीकरण निरीक्षण कर अस्पताल को सील कर दिया। इसके साथ ही, तीनों झोलाछाप डॉक्टरों या कथित संचालकों को नोटिस जारी कर 28 नवंबर, गुरुवार को जिला स्वास्थ्य विभाग को अल्टीमेटम दिया गया है।

पांडेसरा जैसी कुछ अन्य

अस्पतालों के संचालन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या डॉक्टरों ने गुजरात में प्रैक्टिस करने के लिए गुजरात मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराया है या नहीं। पांडेसरा की जनसेवा अस्पताल, जिसे पहले फायर विभाग ने सील किया था, अब जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील किए जाने के बाद

विवाद का केंद्र बन गई है।

इस अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों में से कुछ राज्य के बाहर से हैं। गुजरात में प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टरों के लिए गुजरात मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों की जांच की जाएगी कि क्या उन्होंने गुजरात में पंजीकरण कराया है। यदि उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है, तो नए कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि बिना वैध पंजीकरण के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर रोक लगाई जा सके।

यह स्थिति सूरत के सचिन क्षेत्र की है, जहां किसी भी कार्रवाई का अभाव देखा गया है।

इस क्षेत्र में नाबालिंग बच्चीयों का गर्भपात जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, और यह सब स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दबाव के चलते चल रहा है।



जानकारी के अनुसार, इन क्लीनिकों और अस्पतालों में मरीजों के मेडिकल रिपोर्ट्स भी फर्जी बनाए जाते हैं, और मरीजों का इलाज इसी आधार पर

किया जाता है। यदि कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो भी संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

सूत्रों के मुताबिक, व्यापार मंडल के धन उगाही की। जिन व्यापारियों या दर्ज कराई जाती है, तो भी संबंधित नाम पर राजनीतिक दलों के सचिन क्लीनिक संचालकों ने यह राशि देने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में से इनकार किया, उनके साथ छोटी-छठ पूजा के नाम पर बड़े पैमाने पर मोटी झड़ियें भी हुईं।

सूत्रों के मुताबिक इस क्षेत्र में हिन्दुत्व के नाम पर गंभीर घटनाओं, जैसे गर्भपात को अंजाम दिया जाता है।

ऐसी स्थिति में, जब कानून का उल्लंघन करने वाले ही प्रभावशाली लोगों के साथ हों, तो कोई भी शिकायत दर्ज करने का साहस नहीं करता। इस बजह से इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रही है। शहर के डिंडोली, पांडेसरा, सचिन, सचिन जीआईडीसी, पाली, बमरौली जैसे श्रमिक बहुल इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों ने धड़ल्से से क्लीनिक खोल रखे हैं। बिना किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र के, महज दो से पांच साल तक किसी अस्पताल या क्लीनिक में काम करने के बाद ये लोग डॉक्टर बन बैठे हैं और खुलोआम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

इस अस्पताल के तीन संचालकों -

- बबलू राम आश्रम शुक्ल (पता: ओ. साई पूजा रो हाऊस, भेस्तान),**
- गंगाप्रसाद वैकुंठप्रसाद मिश्रा (पता: ए. गृहम सोसायटी, हनुमान मंदिर के पास, गोडादरा), और**
- राजाराम केशवप्रसाद दुबे (पता: 118ए, त्रिसिनगर, पिलान प्लाइट, पांडेसरा)**

जिला पंचायत के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गए। शुक्रवार देर शाम स्वास्थ्य अधिकारी अनिल पटेल अस्पताल पहुंचे और नए कानून के तहत कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया।

सूत्रों के मुताबिक हिन्दुत्व के नाम पर लोगों का शोषण कर फर्जीवाड़ा कर रहे जमीन के दलाल, बिल्डर, डेवेलोपर, अवैध रूप से चला रहे नाश का करोबार, हिन्दुत्व के नाम पर कर रहे कानून के निति-नियम का उल्लंघन

लोगों की जिंदगी के साथ झोलाछाप डॉक्टरों या संचालकों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें 28 नवंबर, गुरुवार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के तहत कार्रवाई की गई थी, और पुलिस द्वारा भी मामले की जांच

में रखा गया है। इसी दौरान, पांडेसरा की जनसेवा मल्टीस्पेशलिस्ट अस्पताल को लेकर पालिका के फायर विभाग द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, और पुलिस द्वारा भी मामले की जांच की जाएगी। यदि अपने आधार और अन्य प्रमाणों के साथ आगामी 28 नवंबर को उपस्थित होने का अल्टीमेटम दिया गया है।

यदि वे निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो इस एकट के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह स्थिति सूरत के सचिन क्षेत्र की है, जहां किसी भी तरह की कार्रवाई का अभाव देखा जाता है। इस पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने यह कार्रवाई को अधार देखने को मिला करता है।

सूरत

क्रांति समय

अज्ञात हमलावरों ने ऊपर से चप्पू के घाव मारकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया।

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के कापोद्रा क्षेत्र में रात

एक युवक की शब्द सर्वजनिक रूप से हत्या किए जाने से हड्डकंप मच गया है। युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है। युवक का शब्द सर्वजनिक स्थान पर पड़ा हुआ था, जिससे लोगों का जमावड़ा लग गया था। शब्द खन से सना हुआ था। युवक को आसपास के इलाके के लोग पहचानते थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्च पुलिस अधिकारी ने पहुंचकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक की जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्च पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि, हत्या के कारण के बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। पुलिस के लोगों के बारे में यह अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है।

वर्षा क्षेत्र के किरण चौक में 123 नंबर की सूरते अनाज की दुकान पर अनाज कम देकर गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है।

सूरत के वराढ़ा-ए क्षेत्र स्थित किरण चौक में सूरते अनाज की दुकान में सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों को अनाज प्रदान किया जाता है, लेकिन उन्हें निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं दिया जाता, ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

राज्य सरकार द्वारा राज्य की दुकानों में पारदर्शिता के साथ अनाज वितरण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन राशन माफिया अपनी मनमानी से अनाज की हेराफेरी करने में सफल हो जाते हैं। स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण वितरण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन राशन माफिया अपनी जानकारी नहीं दी जाती। उन्होंने दुकान नंबर 123 पर पहुंचकर जांच की जानी वाले भारी व्यक्तियों की जांच की जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन राशन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि इन राशन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि इन राशन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि इन राशन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नह